भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग

****

मासिक मंत्रि मंडल सारांश फरवरी -2021

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

(i) डीबीटी के 35 वें स्थापना दिवस का आयोजन

बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का 35 वां स्थापना दिवस 26 फरवरी, 2021 को सांकेतिक (वर्चुअल) माध्यम से मनाया गया। इस अवसर पर, निम्नलिखित श्रेणियों के तहत बीआरआईटीई पुरस्कार प्रदान किए गए।

क. हरगोविंद खोराना-इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड (15 पुरस्कार)

ख. एस. रामचंद्रन-नेशनल बायोसाइंस अवार्ड फॉर कैरियर डेवलपमेंट (10 पुरस्कार)

ग. जानकी अम्मल-नेशनल वूमेन बायोसाइंटिस्ट अवार्ड (3 अवार्ड; वरिष्ठ श्रेणी के तहत 1 और युवा श्रेणी के तहत 2)

घ. टाटा नवाचार अध्येतावृत्ति (5 पुरस्कार)

ङ. बायोटेक उत्पाद, प्रक्रिया विकास और व्यावसायीकरण पुरस्कार (5 पुरस्कार)

(ii) बायोटेक - प्राइड (डाटा विनिमय के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) नीति:

मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देशानुसार, बायोटेक-प्राइड नीति के संबंध में मंत्रिमंडल नोट पर व्यय विभाग, विधि कार्य विभाग और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से टिप्पणियां मंगाई जा रही हैं।

(iii) हिमालयन जैव संसाधन मिशन

माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन, ने डीबीटी-आईएलएस के 32 वें स्थापना दिवस (18 फरवरी 2021) के अवसर पर "हिमालयन जैव संसाधन मिशन" की शुरूआत की। इस मिशन का मुख्य ध्यान हिमालय के समृद्ध जैव स्रोतों के विकास और उनके स्थायी उपयोग पर होगा।

(iv) कोविड-19 के समाधान के लिए डीबीटी द्वारा किए गए उपाय

क. मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन

"मिशन कोविड सुरक्षा - बीआईआरएसी द्वारा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन" कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन के तहत, विभिन्न समीक्षा

बैठकें आयोजित की गईं। कुल 2 वैक्सीन कैंडीडेट, 3 सुविधाओं और 8 नैदानिक परीक्षण स्थलों के समर्थन के लिए सिफारिश की गई है।

ख. नैदानिक परीक्षण (पीएसीटी) पहल में तेजी लाने के लिए भागीदारी

डीबीटी बीआईआरएसी और सीडीएसए के माध्यम से नैदानिक परीक्षण (पीएसीटी) में तेजी लाने के लिए भागीदारी की शुरूआत की है और विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से मित्र राष्ट्रों में कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों की सुविधा के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। प्रशिक्षण की दूसरी श्रृंखला 05 फरवरी 2021 को शुरू हुई और फरवरी 2021 में जीसीपी (अच्छी नैदानिक पद्धतियां) के चार सत्र आयोजित किए गए; जिसमें अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, केन्या, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सोमालिया और वियतनाम के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग. टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई)

विभाग ने **19** फरवरी, 2021 को आयोजित एनटीएजीआई की स्थायी तकनीकी उप-समिति (एसटीएससी) की बैठक में भाग लिया, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में प्राथमिकता वाले शोध अध्ययनों की सूची पर चर्चा की गई और कोविशील्ड वैक्सीन के खुराक अंतराल की समीक्षा की गई।

घ. परीक्षण/निदान

देशभर के सरकारी संस्थानों में कोविड-19 नमूनों के परीक्षण को बढ़ाने के लिए हब और स्पोक मॉडल में शहर/क्षेत्रीय समूह स्थापित किए गए हैं। ये हब आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों (डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, आईसीएआर आदि) द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं। अब तक 21 शहर/क्षेत्रीय समूहों की स्थापना की जा चुकी है और 29.89 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण भारत में परीक्षण पहुंच को सक्षम करने के लिए, माननीय मंत्री द्वारा 18 जून, 2020 को कोविड परीक्षण के लिए शुरू की गई आई-लैब, (संक्रामक रोग प्रयोगशाला)- मोबाइल लैब ने फरीदाबाद क्षेत्र में लगभग 14858 परीक्षण किए। डीबीटी ने परीक्षण जारी रखने के लिए सभी हबों को जनशक्ति सहायता प्रदान की है।

(v) जैव सुरक्षा

क. विभाग ने क्रमश: 04 और 18 फरवरी, 2021 को आनुवांशिक फेरबदल समीक्षा समिति (आईसीजीएम) की 199वीं बैठक में 30 आवेदनों और 200वीं बैठक में 33 आवेदनों की समीक्षा की। इन आवेदनों में आयात/निर्यात/हस्तांतरण/प्राप्ति यों, सूचना मदों और बायोफार्मा के लिए पूर्व-नैदानिक विषाक्तता अध्ययन, और कृषि के लिए आयात/निर्यात/हस्तांतरण/प्राप्ति यों और स्थल चयन परीक्षण शामिल हैं। प्रत्येक आवेदन पर विचार-विमर्श के बाद, आरसीजीएम द्वारा उचित निर्णय लिया गया।

ख. माह के दौरान, आईबीकेपी पोर्टल पर 26 संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों का गठन किया गया था।

(vi) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) मामले: एससीओएमईटी (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी) मदों के 17 आवेदनों के अनुरोध पर विभाग की टिप्पणियों को डीजीएफटी को सूचित किया गया था।

(vii) किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में आरएफपी पर आधारित नई परियोजनाएँ

क. बायोटेक ऊर्जित (विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त उद्योग परिवर्तन) समूह

विभाग ने देश में बायोटेक ऊर्जित (विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त उद्योग परिवर्तन) बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आमंत्रण के आधार पर 19 अभिरूचि पत्र (एलओआई) प्राप्त हुए, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 है।

(viii) डीबीटी की सामाजिक पहुंच:

क. 26 फरवरी, 2021 को डीबीटी के 35 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में, **"भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास के** 35 **वर्ष - एक रोमांचक यात्रा"** पर एक वेबिनार, एक ई-पुस्तक- **कोविड के खिलाफ डीबीटी की लड़ाई: वायरस से वैक्सीन तक** और विभाग के पशु जैव प्रौद्योगिकी और मत्स्य पालन विभाग का एक ई-सार संग्रह शुरू (लांच) किए गए थे।

ख. "कोविड 19 वैक्सीन का विकास - भारत एक वैश्विक हब" नामक वेबिनार का आयोजन 18 फरवरी, 2021 को डीबीटी और आईआईसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

ग. 18 फरवरी, 2021 को "हिमालयन जैव संसाधन मिशन" के शुभारंभ के दौरान, प्रत्येक कार्यक्रम को परिभाषित करने के लिए विचार मंथन सत्रों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था।

घ. फर्स्ट हब: स्टार्ट-अप और नवाचारकों के लिए नवाचार और विनियमों की सुविधा

फर्स्ट हब एक सुविधा इकाई है जो बीआईआरएसी में डीबीटी द्वारा स्थापित की गई है ताकि नवाचारकों के प्रश्नों को हल किया जा सके। वैश्विक स्तर पर मौजूदा स्थिति के संबंध में, नवाचारकों के प्रश्नों को हल करने के लिए एक माह के दौरान वैकल्पिक शुक्रवार को फर्स्ट हब सत्र आयोजित किया जाता हैं। फरवरी के लिए, कोविड-19 के सत्र 5 फरवरी 2021 को आयोजित किए गए थे और 6 से अधिक प्रश्नों को स्पष्ट किया गया था। विनियामक पाथवे, वित्तपोषण अवसर, सार्वजनिक खरीद, आईवीडी परीक्षण और सत्यापन, मानक और विनिर्देशों, विनिर्माण और परीक्षण बुनियादी ढांचे के समर्थन के बारे में प्रश्न हल करने के लिए सीडीएससीओ, आईसीएमआर, एनआईबी, जीईएम, केआईएचटी, बीआईएस, डीबीटी और बीआईआरएसी के प्रतिनिधि उपलब्ध थे।

ङ. शोधकर्ताओं के लिए आईबीएससी जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में क्रमशः 11 और 25 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11वां तथा 12वां वेबिनार आयोजित किया गया था।

(ix) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. 5 फरवरी, **2021** को राजदूत श्री तन्मय लाल के साथ भारत-स्वीडन संयुक्त नवाचार साझेदारी (जेआईपी) पर एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई थी।

ख. यूरोपिय संघ और भारत के बीच 12 फरवरी, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग संयुक्त संचालन समिति की 13वीं बैठक का आयोजन सांकेतिक रूप में किया गया। श्री जीन-एरिक पिकेट, यूरोपीय आयोग (ईसी) के अनुसंधान और नवाचार के महानिदेशक ने यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया; प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी और डॉ रेणुस्वरुप, सचिव, डीबीटी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

ग. डीबीटी और चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान परिषद् (ई एस आर सी), यूके के बीच "यूके-भारत कोविड-19 साझेदारी पहल" के तहत 30 प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए 23-24 फरवरी, 2021 को सांकेतिक रूप में संयुक्त चयन पैनल की बैठक आयोजित की गई थी।

(x) प्रकाशन और पेटेंट

विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा 76 शोध प्रकाशन और 8 पेटेंट दायर/प्रदान किए गए हैं।

(xi) डीबीटी द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के साथ-साथ डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास/व्यावसायीकरण: 1

क. इन-स्टेम, बेंगलौर में, डॉ. मिन्हाज सिराजुद्दीन, सहायक अन्वेषक/वैज्ञा. ई ने कोशिकाओं के भीतर रेड टाइरो सिनेशन सेंसर में माइक्रो फिलामेंट की पहचान हेतु सेंसर आधारित एक अंतर्कोशिकीय प्रकाश का विकास किया।

ख. डीबीटी-आरजीसीबी से कोविड-घ्राणनाश जांच तकनीक, तिरुवनंतपुरम को इंस्टिगेटर ई-सपोर्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया।

ग. डीबीटी-आरजीसीबी, तिरुवनंतपुरम ने बहु-राष्ट्रीय कंपनी, क्यू बायोमेड को उत्तरोसाइड बी प्रौद्योगिकी अंतरित की और क्यू बायोमेड से पहली बृहत राशि प्राप्त की। उत्तरासाइड बी से आरफन ड्रग उपाधि प्राप्त की।

II. महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट

(i) दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: लागू नहीं

(ii) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों का अनुपालन: उपलब्ध नहीं

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	टिप्पणी
-	-	-

(iii) तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' के मामलों की संख्या: शून्य

(iv) ऐसे मामलों का विवरण जिसमें कार्य के आदान-प्रदान में परिवर्तन हुआ है: शून्य

(v) ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

सक्रिय फ़ाइलों की कुल संख्या: 12493	जनवरी, 2021 के दौरान बनाई गई ई-फाइलों की कुल संख्या- 412

(vi) लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 63	माह के अंत में लंबित लोक शिकायतों की संख्या: 10

(vii) संचालन और विकास में तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए कदम: शून्य

(viii) क. इस बात की पुष्टि करें कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के एसीसी के दायरे में आने वाले सभी पदों के कार्यकाल का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है: यह पुष्टि की जाती है कि मंत्रालय/विभाग (डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्तशासी संस्थानों और उपक्रमों दोनों) में सभी पदों का विवरण एबीसी के दायरे में आने वाले एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है।

ख. एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति उन मामलों के संबंध में एक पैरा जिनमें अलग-अलग शीर्षकों में एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं: यह पुष्टि की जाती है कि एसीसी के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

ग. उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने हैं: सूचित किया जाता है कि इसे 'शून्य' समझा जाए।

(ix) सरकारी ई-बाज़ार (जीईएम) की स्थिति:

फरवरी, 2021 के माह के लिए जीईएम के माध्यम से विभाग द्वारा 11,80,112/- रु. खरीद की गई है।